(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय मूल के जिन विदेशी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का निर्णय लिया गया है उनकी संख्या कितनी है और उक्त छात्रवृत्ति की धनराशि कितनी होगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया था । यह राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सामान्य निकाय की बैठक में एक विशेष अतिथि द्वारा दिया गया सुझाव मात्र ही था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

किसानों के लिए कपास के लाभकारी मूल्य

379. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का रिकार्ड उत्पादन होने के बावजूद किसानों को कपास का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

(ग) क्या सरकार ने आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट का अध्ययन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा समिति की कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं तथा इन सिफारिशों को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं। फिर भी वर्ष 1990-91 के कपास-मौसम के दौरान कपास का उत्पादन मात्र 115 लाख गांठ होने का अनुमान है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिये जाने की आशा है ।

लोक सभा और विधान सभाओं में रिक्त स्थानों की संख्या

380. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के विभिन्न भागों में लोक सभा तथा विधान सभाओं के कितने स्थान रिक्त पड़े हुए हैं ; और

(ख) वहां पर चुनाव प्रक्रिया आरम्भ करके इन स्थानों के लिए कब तक चुनाव कराए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) इस समय लोक सभा के 36 स्थान (इसमें पंजाब राज्य के 13 और जम्मू कश्मीर राज्य के 6 स्थान सम्मिलित हैं, (और विधान सभा के 95 स्थान रिक्त हैं ?

(ख) लोक सभा के 17 रिक्त स्थानों और विधान मण्डलों के 95 रिक्त स्थानों को भरे जाने के लिए निर्वाचन आयोग सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श करके निर्वाचन कार्यक्रम तैयार कर रहा है । पंजाब में निर्वाचन 25 सितम्बर, 1991 को कराया जाना निश्चित किया गया है । जम्मू-कश्मीर राज्य में निर्वाचन कराए जाने के बारे में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है ।

दसवीं लोक सभा के चुनावों में किए गए कदाचारों के संबंध में शिकायतें

381. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं लोक सभा के चुनावों के दौरान किए गए कदाचारों के

संबंध में विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त सभी शिकायतों को चुनाव आयोग द्वारा निपटा दिया गया है ;

(ख) इस प्रकार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उनमें से कितनी शिकायतों को निपटा दिया गया है ; और

(ग) शेष शिकायतों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग के पास विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों से 9. दसवीं लोक सभा निर्वाचनों के दौरान अनाचार की 4356 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । निर्वाचन आयोग को जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, उन पर विचार करके, कार्रवाई की गई थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी व्यय में कटौती करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत तथा महंगाई भत्ते के भुगतान का रद्द किया जाना

382. डा० रत्नाकर पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी व्यय में कटौती करने के लिए छुट्टी रियायत यात्रा सुविधा को रद्द करने और सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के भुगतान को रोकने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shifting of office of Dev. Commr. (Handlooms) from Pune

383. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to shift the Office of the Development Commissioner for Handlooms from Pune; and

(b) if so, what are the reasons therefor and the place to which it is likely to be shifted?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) Yes, Sir. There is an office of the Regional Enforcement Officer at Pune under the Office of the Development Commissioner for Handlooms.

(b) The functions of the Enforcement Office are to implement the Handlooms (Reservation of Articles for Production) Act, 1985. There is a blanket stay of the Supreme Court on the implementation of this Act and the Rules issued thereunder. Thus there is no work in the Enforcement Offices. All the three Enforcement Offices presently working from the rented buildings are being shifted to nearest Weavers Service Centres (WSCs)/ Indian Institute of Handloom Technology (IIHTs) which are subordinate offices of the Office of the Development Commissioner for Handlooms. This is with a view to save expenditure on rent, phone etc. Office at Pune may be eventually shifted to Bombay to be accommodated there in WSC, Bombay.

Closed textile mills in the country

384. DR. ABRAR AHMED: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is the number of textile mills which are closed at present in the country and what are the reasons therefor and the amount of loss being incurred as a result thereof;

(b) what is the number of labourers who have been affected by it;